

अंतरराष्ट्रीय यथार्थवाद की आवश्यकता

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता व महत्त्व से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

21वीं शताब्दी को चीन और भारत की सदी के रूप में समाहित किया गया है। हालाँकि दोनों देशों के राष्ट्रीय हित अंतरराष्ट्रीयता के पालन के साथ संघर्ष में बदल दी जाती है। इसके अलावा हाल ही में हुआ गलवान घाटी संघर्ष या निर्माणाधीन चीन-पाकस्तान आर्थिक गलियारा (जो भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है) में चीन की आक्रामक रणनीति भारत के लिये एक प्रमुख नीतगत चुनौती रही है। जैसा कि भारत के वदेश मंत्री ने कहा है कि भारत के सामने अब एक बड़ी चुनौती यह है कि उसे स्वयं के उदय को सुनिश्चित करते हुए अधिक शक्तिशाली पड़ोसी का प्रबंधन करना है। हालाँकि अंतरराष्ट्रीयता हमेशा भारत की वदेश नीति का एक प्रमुख आधार रहा है, चीन के संबंध में अधिक यथार्थवादी वदेश नीति की आवश्यकता है।

अंतरराष्ट्रीय यथार्थवाद की आवश्यकता

- **लूप-साइड्डेड आर्थिक व्यापार:** भारत में चीन के साथ अधिक व्यापार करने की वकालत ने अब इसकी एकतरफा स्थिति को मज़बूत करने का मार्ग प्रशस्त किया है।
 - व्यापार घाटे में अधिकता के कारण भारत ने चीनी वस्तुओं पर निर्भरता विकसित की है।
 - इस तथ्य को देखते हुए भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी ([Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP](#)) से हाथ खींच लिया क्योंकि भारत के राष्ट्रीय वाणिज्यिक हितों और चीन के नेतृत्व वाले एशियाई आर्थिक क्षेत्रवाद के बीच वरोधाभास था।
- **चीन का वसितारवाद:** चीन अपनी सीमाओं का वसितार करने के लिये एक 'अतार्किक शक्ति' या 'वसितारवादी शक्ति' की तरह व्यवहार कर रहा है।
 - चीन लंबे समय से भारतीय सीमा के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी खंड के क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिये इच्छुक है।
 - BRI परियोजना के माध्यम से चीन का उद्देश्य अपने पड़ोस और संपूर्ण एशिया, यूरोप में भू-रणनीतिक रूप से हावी होना है।
- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** शीत युद्ध के बाद भारत ने एशियनजिम को फरि से अपनाया जब उसने लुक ईस्ट नीति ([Look East Policy](#)) का समर्थन किया और दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ ([Association of South-East Asian Nations](#)) के नेतृत्व में एशियाई क्षेत्रीय संस्थानों में शामिल हो गया।
 - पूर्वी एशिया में आर्थिक क्षेत्रवाद की खोज और वैश्विक बहु-ध्रुवीयता के ज़ोर ने चीन के तेजी से आर्थिक और राजनीतिक परिणामों को गंभीर रूप से कम करके आँका था।
 - चीन स्ट्रिंग्स ऑफ परल (Strings of pearls) और CPEC के माध्यम से भारत पर दबाव बना रहा है।
- **वैश्विक संस्थानों की प्रभावहीनता:** अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने की चाह रखने वाले वैश्विक संस्थानों के निर्माण में उदारवादी अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को अब बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप ब्रेकजटि और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रणनीतिक समन्वय में गरिबत जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं।

भारत की यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय नीति

यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय नीति के चीन के संदर्भ में यह अर्थ होगा कि भारत को चीन के उदय और व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के अंतराल के उद्देश्य आकलन करना चाहिये। इसे समान विचारधारा वाले देशों के साथ समन्वय स्थापना की परकिल्पना भी की जानी चाहिये ताकि शक्ति और क्षेत्रीय शांति के मध्य साम्यता बनाई जा सके। इसके अनुसरण में भारत वदेश नीति की पहल पर ध्यान केंद्रित कर सकता है:

- **पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाना:** भारत पहले से ही U.S. का "नजदीक सहयोगी" रहा है और कई यूरोपीय देशों के साथ उसके रणनीतिक संबंध हैं।
 - चीन को हृदि महासागर तक पहुँचने से रोकने के लिये भारत को हर संभव कोशिश करनी चाहिये।
 - भारत और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वयितनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों के बीच सामरिक अभिसरण की आवश्यकता है ताकि इंडो-पैसिफिक रणनीति तैयार की जा सके और चीन की सैन्य और आर्थिक शक्ति को संतुलित किया जा सके।

- चतुरभुज सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue- Quad) को भी समान वचिारधारा वाले देशों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- इसके अलावा G-7 जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के वसितार और भारत को शामिल करने का प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय मामलों में चीन के प्रभाव को संतुलित करने में सहायक होगा।
- **हार्ड पावर को मज़बूत बनाना:** माउंटेन स्ट्राइक कॉर्पस डिवीजनों को मज़बूत करने और एक थिएटर कमांड स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है।
- **राजनयिक आक्रामक रवैया अपनाना:** भारत को चीन की आक्रामक नीतियों और रणनीतिके वपिरीत अपने शांतपूरण इरादों को उजागर करने की आवश्यकता है।
 - भारत द्वारा अपनाये गये तकनीकी सहायता कार्यक्रम न केवल भारत और अन्य वकिसशील देशों के बीच एक स्थायी संबंध प्रदान करते हैं इसके अतरिकित ये चीनी सहायता से भी नरिपेक्ष हैं।
- **पड़ोस पहले की नीति:** भारत को अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, ईरान, वयितनाम जैसे सहयोगियों पर वशेष रूप से ध्यान देना चाहिये, जो पश्चिम के साथ संबंधों को मज़बूत करने के पक्षधर नहीं है।
 - एशिया के छोटे देश जो लगातार अपने आंतरिक मामलों में चीन के आक्रामक हस्तक्षेप का सामना करते हैं, उन्हें भारत से अधिक समर्थन नहीं मिला है और इसके लिए उन्हें भारत का अधिक सहयोग मलिना चाहिये।
- **आत्मनरिभर बनना:** भारत को अधिक भुगतान करने वाली नौकरियों, प्रौद्योगिकी और तकनीकी के साथ ही नरियात और नविश बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। जसिसे भारत को चीनी आयात से अपनी आर्थिक नरिभरता कम करने और आत्मनरिभरता हासलित करने की आवश्यकता है।

नषिकरष

अगर अभी तक हुई प्रगतिको खतरे में नहीं डालना है तो सीमा पर शांतिकायम होना चाहिये। सीमा और संबंधों के भवषिय को अलग नहीं कयिा जा सकता है। इस प्रकार चीनी शकृता से नषिटने के लिए भारत को अधिक अंतरराष्ट्रीयता की आवश्यकता है। लेकनिय यह एक ऐसा अंतरराष्ट्रीयतावाद होना चाहिये जो यथार्थवाद में नषिति हो और भारत की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमकित्ताओं पर आधारित हो।

REALISM	LIBERALISM
1. States are the only actors at international level.	1. States are not the only actors. Other actors e.g. individuals, IOs, MNCs also play an important role.
2. States are rational actors and aim for their own self interest/ relative gain.	2. States are not rational actors. They aim for absolute gain.
3. Realists believe in maximizing military power in order to achieve peace and security.	3. Liberalists believe that security can be achieved by cooperation, mutual gaining, applying moral/ethical principles.
4. Realists believe in the concept of armament, i.e. states should have arms and weapons for self security.	4. Liberalists believe in the concept of disarmament for self security i.e. cooperation.
5. According to realists international system is anarchic in nature.	5. According to liberalists international system is community based.

मुख्य परीक्षा प्रश्न

भारत की चीन नीतिको अंतरराष्ट्रीय यथार्थवाद में नषिति कयिा जाना चाहिये, जसिसे भारत की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमकित्ताओं के साथ जोड़ा जाना चाहिये। चर्चा कीजिये।